पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या-880/2016

थाना कांड संख्या -16 वर्ष-2000 थाना-करजा जिला-मुजफ्फरपुर से उत्पन्न

==========

1. सच्चिदानंद सिंह
2. मितेन्द्र सिंह
3. सत्येंद्र सिंह सभी पुत्र स्वर्गीय सीता राम सिंह, और सभी निवासी गाँव-फंडा, थाना-करजा, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री मधुसूदन कुमार, अधिवक्ता

श्री शिव शंकर शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, अ.लो.अ.

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973---धारा 374(2), 389(1)--- भारतीय दंड संहिता---धारा 302, 147, 148, 149, 323, 324--- दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील---घायल चश्मदीद गवाहों, हितबद्ध गवाहों की गवाही का साक्ष्य मूल्य---चिकित्सकीय साक्ष्य बनाम मौखिक साक्ष्य----जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा---अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप है कि कुछ भूमि विवाद के कारण उन्होंने मृतक पर और साथ ही पीडब्लू-4 और पीडब्लू-7, जिन्होंने मृतक को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था, पर हथियारों से हमला किया, जिससे उन्हें चोटें आईं।

निष्कर्ष: घायल गवाहों को विशेष दर्जा दिया जाता है और वे अत्यंत मूल्यवान साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं---जहां घटना का कोई गवाह स्वयं घटना में घायल हुआ हो, ऐसे गवाह की गवाही को सामान्यतः बहुत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह ऐसा गवाह होता है जिसके साथ अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी होती है और वह किसी को गलत तरीके से फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर(ओं) को नहीं छोड़ेगा---पीडब्लू-4 और पीडब्लू-7 के साक्ष्य निर्णायक रूप से इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि इन दोनों गवाहों को संबंधित घटना के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों के हाथों चोटें आईं---जब तक कि चिकित्सा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य के साथ असंगत रूप से विरोधाभासी न हो, तब तक चश्मदीद गवाहों की मौखिक गवाही पर संदेह नहीं किया जा सकता---सिर पर हमले का विशिष्ट आरोप है और तदनुसार मृतक के सिर पर दो चोटें पाई गई हैं---यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई असंगत विरोधाभास नहीं है जो अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त हो सकता है----बचाव पक्ष किसी भी तरह का सबूत पेश करने में पूरी तरह विफल रहा है। गवाहों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने के लिए उनसे की गई जिरह में पर्याप्त विरोधाभास --- निकट संबंधी गवाह, जिन्हें चोटें भी आई हैं, वे वास्तविक हमलावरों को कभी नहीं छोड़ेंगे और उन लोगों को फंसाएंगे जो घटना में शामिल नहीं हैं --- जांच अधिकारी से पूछताछ न किया जाना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है, खासकर तब जब अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह होने की संभावना नहीं है --- वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से घायल चश्मदीद गवाहों की ठोस, विश्वसनीय और अडिग गवाही की पृष्ठभूमि में, जांच अधिकारी से पूछताछ न किए जाने का मुद्दा पृष्ठभूमि में चला जाता है क्योंकि यह अधिक महत्व नहीं रखता है और महत्वपूर्ण विचार नहीं बनता है --- अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से, मृतक की हत्या करने का इरादा स्थापित नहीं होता है और

इसके अलावा, अभियोजन पक्ष न तो यह स्थापित कर पाया है, न ही मृतक की हत्या करने के लिए अपीलकर्ताओं की पूर्व नियोजित मानसिकता का आरोप लगाया है --- पूरी घटना क्षण भर के आवेश और आवेश में अचानक हुई लड़ाई में हुई प्रतीत होती है, इसलिए मृतक की मृत्यु कारित करने के इरादे का तत्व गायब प्रतीत होता है - धारा 302 आईपीसी (हत्या) के बजाय, अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 304 भाग II (हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया - अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। (पैरा 27, 30, 32, 34, 37, 41-43, 47)

(2010) 10 एससीसी 259, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1396, एआईआर 1983 एससी 484, एआईआर 1953 एससी 364, (2015) 15 एससीसी 327, एआईआर 1982 एससी 55

*.....**पर भरोसा किया गया।***

*(1996) 2 एससीसी 317, (2000) 9 एससीसी 153, (2021) 3 एससीसी 365, (2018) 8 एससीसी 228, 1995 एससीसी (क्रि) 165, सीआर. अपील संख्या 2006/2023, (2011)14 एससीसी 471 .....**को संदर्भित किया गया।***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

और

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सोनी श्रीवास्तव

सीएवी निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सोनी श्रीवास्तव)

दिनांक: 25-03-2025

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'दं. प्र. सं.' कहा जाएगा) की धारा 389(1) के साथ धारा 374(2) के अंतर्गत करजा थाना कांड संख्या 16/2000 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 276/2002 में मुजफ्फरपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 05.08.2016 और 10.08.2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (जिसे आगे 'भा.दं.सं.' कहा जाएगा) की धारा 149 के साथ धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और उन्हें 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और ऐसा न करने पर उन्हें तीन महीने के साधारण कारावास की सजा काटने का निर्देश दिया गया है। अपीलकर्ताओं को भा.दं.सं. की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया है और 2 साल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, अपीलकर्ताओं को भा.दं.सं. की धारा 147 और भा.दं.सं. की धारा 323 और 324 के तहत भी दोषी ठहराया गया है, हालांकि, इसके तहत कोई अलग से सजा नहीं दी गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया गया है।

2. सूचक लाल बाबू सिंह, जिसका फर्दबयान दिनांक 09.02.2000 को 12:30 अपराह्न सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर में दर्ज किया गया था, के फर्दबयान पर आधारित प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि उसी दिन अर्थात दिनांक 09.02.2000 को लगभग 07:30 पूर्वाह्न में जब सूचक अपनी दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था, अभियुक्तगण सचिदानंद सिंह (अपीलकर्ता संख्या 1), मितेंद्र सिंह (अपीलकर्ता संख्या 2), सत्येंद्र सिंह (अपीलकर्ता संख्या 3), मिंटू सिंह और सकल महतो अपने ट्रैक्टर पर आये और जमीन से संबंधित कुछ बातचीत के लिए खेत पर चलने को कहा। इस प्रकार पूछने पर सूचक अपने भाई राज किशोर सिंह के साथ खेत पर चला गया, जबकि अभियुक्तगण पहले से ही अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर वहां पहुंच

चुके थे। बाद में पहुंचे दोनों भाइयों ने देखा कि आरोपीगण उनके खेत से सरसों की फसल काट रहे थे तथा विरोध करने पर आरोपीगण गाली-गलौज करने लगे, जिसका विरोध सूचक ने किया। इसी बात पर सच्चिदानंद सिंह (अपीलार्थी संख्या 1) ने ट्रैक्टर में पहले से छिपाकर रखा फरसा निकाल लिया तथा उसके पुत्र मिंटू सिंह ने कमर में छिपाकर रखा चाकू निकाल लिया। सत्येंद्र सिंह (अपीलार्थी संख्या 3), मितेंद्र सिंह (अपीलार्थी संख्या 2) तथा सकल महतो भी ट्रैक्टर से लाठी-डंडे लेकर आ गए तथा सभी ने मिलकर सूचक तथा मृतक पर जान से मारने की नीयत से लाठी, फरसा तथा चाकू से हमला कर दिया। सूचक के बड़े भाई राज किशोर सिंह (मृतक) के सिर पर फरसा और लाठी से अंधाधुंध हमला किया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। सूचक का आरोप है कि उस पर भी लाठी, डंडा और फरसा से हमला किया गया, जिससे उसके दाहिने हाथ की उंगली में चोट आई, जिससे खून बह रहा था। सूचक द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि बगल के खेत में काम कर रहे उसके चचेरे भाई बीरेंद्र सिंह (अ. सा. -7) सूचक और मृतक को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उस पर भी लाठी और डंडा से हमला किया गया, जिससे उसके दाहिने कलाई पर चोट आई। सूचक का भाई राज किशोर सिंह खून बहते हुए बेहोशी की हालत में पड़ा था और उसे मरा हुआ समझकर आरोपीगण घटनास्थल से भाग गए। इस दौरान हो-हल्ला होने लगा, जिसके बाद अगल-बगल के खेतों में काम कर रहे लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए, जिसके बाद आरोपीगण कटे हुए सरसों की फसल को ट्रैक्टर पर रखकर भाग गए। इसके बाद बताया गया है कि सूचक व अन्य लोग गांव की ओर भागे और एक जीप लेकर अपने भाई राज किशोर सिंह को लेकर बीरेंद्र कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, जीवछ सिंह, पवन सिंह, कालिका सिंह, जालिम सिंह व अन्य को लेकर सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना का

कारण बताया गया है कि आरोपीगण उस जमीन को हड़पना चाहते थे, जिसे सूचक के भाई राज किशोर सिंह ने जीवछ देवी व उर्मिला देवी से रजिस्ट्री कराया था।

3. उपर्युक्त फर्दबयान के आधार पर करजा थाना कांड संख्या 16/2000 दिनांक 10.02.2000 को प्रातः 10.00 बजे धारा 147, 148, 149, 323, 324 एवं 307 भादवि के अन्तर्गत कायम किया गया तथा तत्पश्चात दिनांक 21.02.2000 के आदेश द्वारा भादवि की धारा 302 भी जोड़ी गई। पांच अभियुक्तों सचिदानंद सिंह (अपीलकर्ता संख्या 1), सत्येंद्र सिंह (अपीलकर्ता संख्या 3), मितेंद्र सिंह (अपीलकर्ता संख्या 2), मिंटू कुमार एवं सकल महतो के विरुद्ध प्राथमिकी कायम की गई। जांच के बाद अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307 और 302 के तहत 15.06.2000 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद सभी पांचों नामजद आरोपियों के खिलाफ उन्हीं धाराओं के तहत दिनांक 04.07.2000 के आदेश के तहत संज्ञान लिया गया। मामला 18.04.2002 को सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया और सत्र परीक्षण संख्या 276/2002 के रूप में क्रमांकित किया गया, हालांकि दो आरोपियों के मुकदमे को इस तथ्य के कारण विभाजित किया गया कि एक सकल महतो को उस समय फरार घोषित किया गया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई और दूसरे आरोपी मिंटू कुमार को किशोर घोषित किया गया था, इसलिए उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया। विद्वान विचरण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2003 को अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 302/149, 307/149, 324 और 323 के अंतर्गत आरोप तय किए गए थे।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को पुष्ट करने के लिए, मुकदमे के दौरान 10 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें अ. सा. -1 जालिम सिंह (मृतक का चचेरा भाई), अ. सा. -2 जूली कुमारी (मृतक की बेटी), अ. सा. -3 प्रमोद कुमार सिंह, (मृतक का

चचेरा भाई), अ. सा. -4 लाल बाबू सिंह (खुद सूचक और मृतक का भाई), अ. सा. -5 (डॉ. धीरेंद्र प्रसाद सिंह), जिन्होंने दो घायल गवाहों अ. सा. -7 (बीरेंद्र सिंह) और अ. सा. -4 (लाल बाबू सिंह) से पूछताछ की, अ. सा. -6 (जय राम सिंह), जिन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है, अ. सा. -7 (बीरेंद्र सिंह), जो एक घायल चश्मदीद गवाह है और फर्दबयान पर हस्ताक्षरकर्ता भी है, अ. सा. -8 (जीवच सिंह), जिन्हें अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित किया है, अ. सा. -9 (डॉ. अरुण कुमार सिंह), जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया मृतक और अ.सा. -10 (श्याम सुन्दर सिंह) जो एक औपचारिक गवाह है और उसने औपचारिक एफ.आई.आर. साबित कर दिया है, जिसे प्रदर्श-4 के रूप में चिन्हित किया गया है।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मधुसूदन कुमार द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर आते हुए, उनका पहला निवेदन यह है कि मृतक पर हमले के संबंध में मौखिक आरोप चिकित्सा साक्ष्य से पुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि सभी गवाहों ने लगातार यह बयान दिया है कि अपीलकर्ता संख्या 1 अर्थात् सचिदानंद सिंह ने मृतक राज किशोर सिंह पर फरसा के माध्यम से हमला किया था, जबकि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले अ.सा. -9 (डॉ. अरुण कुमार सिंह) के साक्ष्य से पता चलता है कि कोई तेज काटने की चोट नहीं है, बल्कि मौत का कारण निस्संदेह सिर पर लगी चोट है, लेकिन किसी कठोर और कुंद वस्तु और उसके प्रभाव से हुई है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अन्य अभियुक्तों द्वारा मृतक पर हमला करने के आरोप के विपरीत, अ.सा. -9 (डॉ. अरुण कुमार सिंह) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें शरीर के अन्य भागों पर चोट नहीं मिली है, लेकिन सिर पर दो टांके लगे हुए घाव मिले हैं।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि सभी गवाह एक-दूसरे से संबंधित हैं और यद्यपि घटना खुले मैदान में हुई है, लेकिन अभियोजन

पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह सामने नहीं आया है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर कोई जब्ती सूची नहीं है और वास्तव में न तो खून से लथपथ मिट्टी और न ही इस्तेमाल किए गए हथियार जांच एजेंसी द्वारा जब्त किए गए थे। इससे उनकी अगली दलील यह भी सामने आती है कि मामले के जांच अधिकारी से मुकदमे के दौरान पूछताछ नहीं की गई, जिससे बचाव पक्ष को नुकसान पहुंचा है।

7. साक्षियों की गवाही की सत्यता के संबंध में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान अ.सा. -1 (जालिम सिंह) की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि वह अस्सी वर्ष का व्यक्ति है और चूंकि वह अपने *स्नानगृह* में था, इसलिए उसके लिए खेत में हुई घटना को देखना संभव नहीं था। अ.सा. -2 (जूली कुमारी) के साक्ष्य पर इस आधार पर आपत्ति की गई है कि वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं लगती, हालांकि वह अपने जिरह के पैराग्राफ 2 के मद्देनजर खुद को प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा कर रही है, जिसमें मृतक और सूचनाकर्ता के खेत में जाने की बात कही गई है, लेकिन वह खुद के उनके साथ खेत में जाने या बाद में वहां जाने के बारे में नहीं कहती है। अ. सा. -3 (प्रमोद कुमार सिंह) के संबंध में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलील यह है कि उन्होंने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के समय वह घर पर थे और वह घटनास्थल पर हुल्ला से आए और राज किशोर सिंह को खून से लथपथ पाया। हालांकि, अगले ही पल गवाह ने घटना को देखने की बात कही है, लेकिन पिछले बयान से कुछ हद तक यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने वास्तविक घटना नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने आरोपियों को अपने-अपने हथियारों से लैस देखा था। हालांकि, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता दो घायल चश्मदीद गवाहों अ. सा. -4 (लाल बाबू सिंह) और अ. सा. -7 (बीरेंद्र सिंह) के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाए हैं, लेकिन

इस तथ्य के लिए कि वे संबंधित और हितबद्ध गवाह हैं और इसलिए, उन्होंने अपीलकर्ताओं के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाते हुए उन्हें फंसाया है।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया है कि चूंकि अभियोजन पक्ष मृतक की मृत्यु कारित करने के किसी भी इरादे या उद्देश्य को दर्शाने में पूरी तरह से विफल रहा है और चूंकि उपस्थित परिस्थितियों से पता चलता है कि घटना क्षणिक आवेग में हुई, जिसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ गालियां और प्रतिरोध किया गया तथा यह भी तथ्य कि इस आरोप के बावजूद कि अभियुक्तगण फरसा से लैस थे, मृतक पर कोई तेज काटने वाला घाव नहीं पाया गया, वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के दायरे में नहीं आता, बल्कि मृतक की मृत्यु कारित करने के किसी भी इरादे के अभाव में यह अधिक से अधिक भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के प्रावधान को आकर्षित कर सकता है।

9. आगे बढ़ने से पहले, हम अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णयों पर चर्चा करना चाहेंगे। जांच अधिकारी की गैर-परीक्षण के बिंदु पर ***2019(2) पीएलजेआर 1171 (मुन्ना गोप बनाम बिहार राज्य)*** में प्रकाशित किए गए केस लॉ का संदर्भ दिया गया है और उक्त निर्णय के पैराग्राफ-16 पर भरोसा किया गया है, हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां अलग-अलग होने के कारण, हम वर्तमान मामले में उक्त निर्णय को लागू नहीं पाते हैं। आगे 1***999(3) ऑल पीएलआर 328 (नागेश्वर साओ बनाम बिहार राज्य)*** में प्रकाशित किए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है और उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 9, 13, 15 और 16 का संदर्भ दिया गया है। यह निर्णय संबंधित गवाहों की गवाही से संबंधित है और संबंधित और इच्छुक गवाहों के ऐसे साक्ष्य की अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए, हालांकि, शेष निर्णय उक्त मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर दिया

गया है, ऐसे में हम पाते हैं कि यह विवाद का विषय नहीं है कि संबंधित गवाहों के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने ***2023(2) पीएलजेआर 835 (रमेश चौधरी बनाम बिहार राज्य)*** में प्रकाशित किए गए एक निर्णय पर भी भरोसा किया है और पैराग्राफ संख्या 14 और 19 का उल्लेख किया है, जिसके अवलोकन पर, हम एक बार फिर पाते हैं कि उक्त निर्णय तथ्यों और परिस्थितियों के एक अलग सेट और पैराग्राफ संख्या में पारित किया गया है। धारा 19 विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के कर्तव्य से संबंधित है कि वह वैज्ञानिक विशेषज्ञ साक्ष्य द्वारा साबित करे कि अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार पुलिस द्वारा जांच के दौरान जब्त किया गया था, हालांकि मामले के तथ्य काफी अलग हैं और वर्तमान मामले में स्थिति ऐसी है कि हथियार की कोई जब्ती नहीं दिखाई गई है, हम इस निर्णय को वर्तमान मामले पर लागू नहीं पाते हैं। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में हुई देरी के मुद्दे को उठाने के लिए ***2019(1) पीएलजेआर 571 (आनंद सिंह बनाम बिहार राज्य)*** में प्रकाशित किए गए निर्णय पर भरोसा किया है। हालांकि, वर्तमान मामले में, हम नहीं पाते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई देरी हुई है, बल्कि सूचना देने वाले का फर्दबयान उसी दिन दर्ज किया गया था जिस दिन घटना हुई थी, यानी 09.02.2000 को दोपहर 12:30 बजे। जिसके बाद 10.02.2000 को उक्त फर्दबयान के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई। इसलिए, यह निर्णय भी वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है।

10. अब राज्य के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि धारा 149 भ.दं.सं. की सहायता से की गई है और एफआईआर में मृतक की मृत्यु का कारण बनने के सामान्य उद्देश्य से अवैध रूप से एकत्रित होने वाले पांच

आरोपियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, जो स्पष्ट रूप से भ.दं.सं. की धारा 149 के साथ धारा 302 को आकर्षित करते हैं। राज्य के विद्वान वकील ने आगे कहा कि साक्ष्य की गुणवत्ता हमेशा एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु होती है और वर्तमान मामले में इस तथ्य के बावजूद कि गवाह एक दूसरे से संबंधित हैं, एक तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष के कम से कम दो गवाह अ. सा. -4 (लाल बाबू सिंह) और अ. सा.-7 (बीरेंद्र सिंह) घायल चश्मदीद गवाह हैं, इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि उनकी गवाही अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य है, क्योंकि एक व्यक्ति भले ही संबंधित हो, वास्तविक हमलावर को नहीं छोड़ेगा और दूसरी बात यह कि घायल गवाहों की गवाही कमोबेश घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति को स्थापित करती है।

11. इन दलीलों के अलावा, राज्य के विद्वान स. लो. अ. द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अ. सा. -4 ने स्वयं सुचक होने के नाते अपने फर्दबयान के रूप में एक त्वरित बयान दिया है और अ. सा.-7 (बीरेंद्र सिंह) उक्त फर्दबयान पर हस्ताक्षरकर्ता है। राज्य के विद्वान वकील ने इस तथ्य पर भी जोर दिया है कि दो घायल अभियोजन पक्ष के गवाहों की चोट रिपोर्ट भी प्रदर्श-2 और 3 के रूप में रिकॉर्ड पर हैं, जिन्हें अ. सा. -5 (डॉ. धीरेंद्र प्र. सिंह) द्वारा विधिवत साबित किया गया है, जिन्होंने दो घायल गवाहों की जांच की थी। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अ.सा. -1 (जालिम सिंह) के संबंध में दिए गए इस तर्क के जवाब में कि वह अपने स्नानघर में था और इस प्रकार उसके लिए घटना को देखना संभव नहीं था, हमारा ध्यान अ.सा. -4 (सूचनाकर्ता) के साक्ष्य की ओर आकृष्ट किया गया है, जैसा कि पैराग्राफ-2 में दर्ज है, जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उक्त *स्नानघर* घटनास्थल अर्थात खेत के निकट है। ऐसे साक्ष्य के आधार पर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अ.सा.-1 (जालिम सिंह) के घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने की

संभावना को खारिज करना बेबुनियाद है। इसी प्रकार, उन्होंने अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता पर भी जोर दिया है।

12. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के अलावा, हमने मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन किया है। आगे बढ़ने से पहले, साक्ष्यों पर सरसरी तौर पर चर्चा करना आवश्यक है।

13. अ.सा. -1 (जालिम सिंह) मृतक का चचेरा भाई है और घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा भी करता है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के समय वह अपने स्नानघर में था, उसने अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों को विभिन्न हथियारों से लैस देखा, जो मृतक राज किशोर सिंह पर हमला कर रहे थे और बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस गवाह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि मृतक उसका भाई था, हालांकि, वे अपने घर और जमीन जायदाद के मामले में अलग-अलग रहते थे। अ.सा.-1 ने अपनी जिरह में आगे कहा है कि उसने जांच अधिकारी के समक्ष कहा था कि सचिदानंद सिंह (अपीलकर्ता संख्या 1) ने फरसा से अपीलकर्ताओं पर हमला किया था जबकि मिंटू सिंह ने चाकू से हमला किया था। उन्होंने जांच अधिकारी के समक्ष कहा था कि उन्होंने राज किशोर सिंह (मृतक) को घटनास्थल पर घायल और बेहोशी की हालत में देखा था, उनके सिर और नाक से खून बह रहा था, जिसके चलते राज किशोर सिंह को सुबह 8:00-9:00 बजे अस्पताल ले जाया गया था। उन्होंने कहा है कि वे अस्पताल नहीं गए थे और जांच अधिकारी ने उसी दिन उनका बयान लिया था और यह कहना गलत होगा कि उनका बयान ढाई महीने बाद लिया गया।

14. अ. सा.-2, जूली कुमारी मृतक की बेटी है और वह भी चश्मदीद गवाह होने का दावा करती है। अपने मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि घटना सुबह 7:00 बजे हुई थी और उसके पिता राज किशोर सिंह (मृतक) पर सचिदानंद सिंह

(अपीलकर्ता संख्या 1) ने फरसा से, मिंटू सिंह ने चाकू से तथा सत्येंद्र सिंह (अपीलकर्ता संख्या 3), महेंद्र सिंह और सकल महतो ने लाठी से हमला किया था, जिससे उसके पिता घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, मृतक की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसने आगे दावा किया है कि वह आरोपियों को पहचानती है। अपनी जिरह में अ.सा.-2 जूली कुमारी ने कहा है कि उसके पिता सुबह 7:00 बजे अपने चाचा जो कि सूचक हैं (अ.सा.-4) के साथ खेत पर गए थे। उसने यह भी कहा है कि मृतक को अस्पताल ले जाया गया और उसे घर नहीं लाया गया। उसने अंत में एक सामान्य बयान दिया है की वह खेत में जाती है।

15. प्रमोद कुमार सिंह (मृतका का चचेरा भाई) से अ. सा.-3 के रूप में पूछताछ की गई और उसने भी प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करते हुए कहा कि घटना साढ़े तीन साल पहले सुबह 07:30 बजे की है, जब वह घर पर था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि शोर मचाया गया, जिसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंचा और राज किशोर सिंह को खून से लथपथ पाया। हालांकि, उसने अगले ही पल कहा कि उसने सचिदानंद सिंह (अपीलकर्ता नंबर 1), मितेंद्र सिंह (अपीलकर्ता नंबर 2), सकल महतो और मिंटू सिंह को हमला करते देखा। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने सचिदानंद सिंह (अपीलकर्ता संख्या 1) को फरसा से लैस, सत्येंद्र सिंह (अपीलकर्ता संख्या 3), सकल महतो को लाठी से लैस और मिंटू सिंह को चाकू से लैस होकर राज किशोर सिंह (मृतक) पर हमला करते देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि लाल बाबू सिंह यानी सूचक (अ. सा. -4) और बीरेंद्र सिंह (अ. सा. -7) भी घटना के दौरान घायल हो गए, हालांकि वह यह नहीं बता सकते कि लाल बाबू पर किसने हमला किया। इस गवाह ने आगे कहा है कि राज किशोर सिंह को जालिम सिंह (अ. सा. -1) के बथान में लाया गया और जीप पर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें आगे के इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां अंततः उनकी मृत्यु हो गई। जिरह में उसने मृतका से अपने रिश्ते के

बारे में बताया है कि वह उसकी चचेरी बहन है और यह भी बताया है कि उसका घर राज किशोर सिंह के घर से सटा हुआ है।

16. अगला गवाह जिसका साक्ष्य महत्वपूर्ण है, वह लाल बाबू सिंह (वर्तमान मामले का सूचक) है, जिसकी जांच अ. सा.-4 के रूप में की गई है। वह मृतक का भाई और घायल चश्मदीद गवाह भी है। इस गवाह ने घटना का चश्मदीद बयान देते हुए अपने फर्दबयान में दिए गए कथन पर कायम है। उसने बताया है कि एफआईआर में नामजद सभी पांचों आरोपी ट्रैक्टर पर सवार होकर आए और खेत में आने को कहा, जिसके बाद वे घटनास्थल पर भी गए, जहां आरोपी सरसों की फसल काट रहे थे, जिसका सूचक और अन्य ने विरोध किया। विरोध करने पर सचिदानंद सिंह (अपीलकर्ता संख्या 1) ने राज किशोर पर फरसा से हमला किया, मितेंद्र सिंह (अपीलकर्ता संख्या 2) और अन्य ने भी लाठी से हमला किया, जिससे मृतक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद मृतक को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इस साक्षी ने कहा है कि उसने पीएमसीएच में अपना बयान दिया था तथा फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है, जिसे प्रदर्श-1 के रूप में अंकित किया गया है। जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि घटनास्थल के पास कोई घर नहीं था, बल्कि जालिम सिंह (अ. सा.-1) का *बथान* था। उसने आगे यह भी कहा है कि घटनास्थल एक खेत है, जहां सरसों की फसल बोई गई थी, जो राज किशोर सिंह की थी तथा सरसों की फसल काटने के कारण हमला हुआ। बताया गया है कि सूचक तथा अन्य लोग अभियुक्तों के घटना स्थल पर पहुंचने के 15-20 मिनट बाद पहुंचे थे।

17. इस साक्षी (अ. सा.-4) ने आगे कहा है कि अभियुक्तों के हाथ में दरांती थी, जबकि सूचक तथा मृतक के पास हथियार नहीं थे। विवाद शुरू होने के बाद उसका भतीजा भी घटनास्थल पर पहुंचा तथा वे कुल छह व्यक्ति थे, जिनमें से दो व्यक्तियों पर

अभियुक्तों ने हमला किया। उसका दावा है कि वह भी वहीं खड़ा था और उसे 4-5 बार लाठियों से मारा गया तथा चाकू से भी चोटें आईं। इस गवाह ने आगे दावा किया है कि उसके बाद उसका भाई भी घायल हुआ। उसने आगे कहा है कि उसके भाई को बचाने के लिए छह लोग गए थे, जिसने घटना को देखा था तथा उसे लगी चोटों का हवाला देते हुए उसने कहा है कि उसे उंगली और कलाई पर चोटें आईं, जबकि राज किशोर सिंह (मृतक) के सिर और छाती पर चोटें आईं, लेकिन उसके शरीर के अन्य हिस्से पर कोई चोट नहीं आई। उसने यह भी कहा है कि मृतक को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था। अपनी आगे की जिरह में अ.सा.-4 ने कहा है कि पुलिस ने उसके भाई यानी मृतक का बयान सदर अस्पताल में उसकी मौजूदगी में दर्ज किया था। उन्होंने अन्य गवाहों के साथ अपने संबंधों का भी खुलासा किया और बचाव पक्ष द्वारा दिए गए सुझाव से इनकार किया कि घटना के दौरान अभियुक्तों पर भी हमला किया गया था और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भी भर्ती कराया गया था। उन्होंने उसी घटना से संबंधित करजा थाना कांड संख्या 20/2000 के एक अन्य मामले के बारे में भी अपनी पूरी अनभिज्ञता व्यक्त की।

18. विचारणीय अगला गवाह डॉ. धीरेंद्र प्रसाद सिंह (अ. सा. -5) हैं, जिन्होंने अ. सा. -7 बीरेंद्र कुमार सिंह और अ. सा. -4 लाल बाबू सिंह की चोटों की जांच की है। अ. सा. -5 ने बीरेंद्र कुमार सिंह, अ. सा.-7 की जांच की और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:-

(1) बायीं बांह पर 1″x1″ आकार की खरोंच के साथ सूजन।

(2) बायीं तर्जनी पर 1/2″x1/2″ आकार की खरोंच।

(3) दायीं कलाई पर 1″x1″ आकार की सूजन।

उन्होंने कहा कि इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति कठोर और कुंद पदार्थ की थी, जबकि लगी चोट की प्रकृति साधारण थी, जो छह घंटे के भीतर लगी।

19. अ. सा. -5 ने उसी दिन यानी 09.02.2000 को 11:00 बजे लाल बाबू सिंह, अ. सा. -4 की चोटों की भी जांच की और उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:-

(1) दायीं तर्जनी पर 1"x1/4" आकार का तेज घाव।

(2) दायीं मध्यमा पर 1/4"x1/4" आकार का तेज घाव।

(3) बायीं बांह पर 1/2"x1/2" आकार की सूजन। (4) बायीं पिंडली पर 1"x1" की सूजन।

अ. सा. -5 ने कहा है कि चोटें नं. 1 और 2 धारदार हथियार से लगी हैं, जबकि चोटें नं. 3 और 4 किसी कठोर कुंद पदार्थ से लगी हैं। उसने चोटों की प्रकृति को साधारण बताया है और चोट का समय छह घंटे के भीतर बताया है। इस गवाह ने दोनों चोटों की रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है और उन्हें क्रमशः प्रदर्श-2 और प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नित किया गया है। उसने यह भी कहा है कि लाल बाबू सिंह की चोटें नं. 1 और 2 धारदार हथियार जैसे फरसा से लगी हो सकती हैं, हालांकि, साक्ष्य से पता चलता है कि इस गवाह से बचाव पक्ष द्वारा बार-बार बुलाने पर भी जिरह नहीं की गई।

20. दो गवाहों अ.सा. -6 जय राम सिंह और अ.सा. -8 जीवच सिंह ने अपने साक्ष्य में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, इसलिए अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। इस मामले को देखते हुए, जब उनकी जिरह में भी कुछ ठोस नहीं आया, तो हम इन दो गवाहों के साक्ष्य पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

21. अ.सा.-7 बीरेंद्र सिंह, जो मृतक का चचेरा भाई है, भी एक घायल चश्मदीद गवाह है। उसने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक 09.02.2000 को प्रातः 07:00 बजे की है, जब वह घटनास्थल के बगल के खेत में काम कर रहा था। उसका दावा है कि उसने एफआईआर में दर्ज सभी पांचों आरोपियों को लाठी और फरसा से लैस होकर घटनास्थल पर आते और मृतक राज किशोर सिंह, जो पहले से ही खेत में मौजूद था, के साथ झगड़ा करते देखा था। उन्होंने सचिदानंद सिंह (अपीलार्थी संख्या 1) द्वारा मृतक के सिर पर फरसा से प्रहार करने का विशेष उल्लेख किया है, जो उसके सिर के पिछले हिस्से में लगा, इसके अलावा अन्य लोगों ने भी मारपीट की, जिससे राज किशोर सिंह (मृतक) जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। इस साक्षी ने कहा है कि उन्होंने लाला सिंह उर्फ लाल बाबू सिंह के साथ मिलकर राज किशोर को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उन पर भी हमला किया। इसके बाद वे लोग घायल अवस्था में राज किशोर को मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टर ने उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां पूरी रात उनका इलाज चला, लेकिन 10.02.2000 को उनकी मौत हो गई और फिर पीएमसीएच में उनका पोस्टमार्टम किया गया। इस साक्षी ने आगे कहा है कि उनके और लाल बाबू सिंह के बयान पर मामला कायम किया गया और सदर अस्पताल में बयान दर्ज किया गया। उन्होंने आगे कहा है कि लाल बाबू सिंह का बयान उनकी उपस्थिति में दर्ज किया गया था तथा उन्होंने उक्त फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर किया था, जिसे प्रदर्श-1/1 के रूप में अंकित किया गया है। जिरह के दौरान उन्होंने इस तथ्य को दोहराया है कि वे अपने खेत में सिंचाई का कार्य कर रहे थे, जब आरोपीगण घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा है कि घटना के समय शोर मचने पर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, जिनमें जालिम सिंह (अ. सा. -1), जीवछ सिंह (अ. सा.-8), जयराम सिंह (अ. सा.-6), पदारथ सिंह, कालिका सिंह, प्रमोद कुमार सिंह (अ. सा.-3), सुरेन्द्र सिंह व अन्य शामिल थे। उन्होंने कहा है

कि मृतक को अस्पताल ले जाया गया, उस समय उसकी नाक से खून बह रहा था तथा वह बेहोश था, हालांकि मृतक के शरीर के अन्य हिस्सों पर उसे मारपीट या चोट का कोई निशान नहीं दिखा। अपने जिरह में उन्होंने यह भी कहा है कि घटनास्थल पर उन्होंने खून देखा था और उक्त जमीन पर सरसों की फसल थी। हालांकि उन्होंने कहा है कि अपीलकर्ता संख्या 1, सचिदानंद सिंह उक्त जमीन पर कोई दावा नहीं कर रहे थे। उनकी आगे की जिरह से यह संकेत मिलता है कि उन्होंने कहा है कि यह तथ्य नहीं है कि उन्होंने कथित रूप से घटना को देखने के संबंध में जांच अधिकारी के समक्ष कोई बयान नहीं दिया था।

22. अ. सा.-9 डॉ. अरुण कुमार सिंह वह डॉक्टर हैं, जिन्होंने 10.02.2000 को अपराह्न 01:15 बजे पीएमसीएच, पटना में मृतक राज किशोर सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया था। इस तरह की जांच में डॉक्टर ने पाया कि पूरे शरीर पर कठोर मृत शरीर मौजूद था, हालांकि, कोई सड़न नहीं थी। उन्होंने सिर पर पट्टी बंधी हुई पाई थी और मृतक के शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व बाहरी और आंतरिक चोटें पाई थीं।

> *(1) नाक के पुल से 3 इंच की मध्य रेखा में खोपड़ी पर 1 इंच लंबाई का एक टांके का घाव।*
>
> *(2) खोपड़ी के दाईं ओर 1 इंच लंबाई का एक टांके का घाव दाईं भौंह के मध्य से 1 इंच दाईं ओर 4 इंच और दाएं कान से 5 इंच।*
>
> विच्छेदन पर:-
>
> *खोपड़ी के नीचे हेमाटोमा ललाट दाएं टेम्पोरल दाएं पार्श्विका और पश्चकपाल क्षेत्र के दाईं ओर पाया गया। 9 इंच x 7 इंच क्षेत्र पर एक संचारित फ्रैक्चर जिसमें ललाट बाएं और दाएं टेम्पोरल, दाएं पार्श्विका और दाएं पश्चकपाल हड्डी शामिल है।*

मस्तिष्क के दोनों तरफ एक्स्ट्राड्यूरल और सबड्यूरल हेमाटोमा पाया गया, खासकर दाईं ओर। सामान्य तौर पर, सभी विसरा कंजेस्टेड पाए गए। पेट में लगभग 250 मिली मिट्टी के रंग का तरल पदार्थ था। मूत्राशय खाली था।

डॉक्टर की राय में मृतक की मृत्यु से लेकर जांच के समय तक का समय लगभग 12 घंटे था और मृत्यु का कारण सिर में चोट लगना था। डॉक्टर ने आगे कहा है कि कठोर और कुंद वस्तु और उसका प्रभाव हिंसा की प्रकृति का था और आगे कहा है कि चोट संख्या 1 और 2 पर राय सर्जन से प्राप्त की जा सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक फोटो कॉपी है जिसे उक्त गवाह ने अपनी लिखावट में लिखा था और उसके द्वारा हस्ताक्षरित भी किया गया था, जिस पर पहचान के लिए 'X' अंकित किया गया है। जिरह के दौरान अ.सा.-9 ने कहा है कि मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके पास नहीं है, उसने चोटों की उम्र नहीं लिखी है और उसे टांके लगाने से पहले चोटों को देखने का अवसर नहीं मिला, साथ ही उसने यह भी कहा है कि गिरने पर इस तरह की चोट संभव नहीं है। डॉक्टर ने भी अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे मृतक के शरीर के किसी अन्य भाग पर कोई अन्य चोट नहीं मिली।

23. अंतिम गवाह श्याम सुंदर सिंह, जिसकी अ.सा.-10 के रूप में जांच की गई, एक औपचारिक गवाह है और उसने एफआईआर के लेखक निरंजन उरांव, जो उस समय थाने के प्रभारी अधिकारी थे, की लिखावट की पहचान करके औपचारिक एफआईआर को साबित किया है। औपचारिक एफआईआर को प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नित किया गया है।

24. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद करने के बाद, विद्वान विचरण न्यायालय ने 16.02.2016 को धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ताओं के बयान दर्ज किए

ताकि वे अपने खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट कर सकें, हालांकि, उन्होंने अपने बयानों में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और सिर्फ इतना कहा है कि वे लिखित स्पष्टीकरण देंगे।

25. बचाव पक्ष ने न्यायालय के विचारार्थ कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। एल.डी. ट्रायल जज ने साक्ष्य की सराहना, विश्लेषण और जांच के बाद अपीलकर्ताओं के दोषी होने का निष्कर्ष निकाला है और उन्हें अपने निर्णय और आदेश के माध्यम से कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

विश्लेषण और विचार

26. हमने एल.डी. ट्रायल जज के विवादित निर्णय, रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री का अवलोकन किया है और एल.डी. द्वारा किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है। अपीलकर्ताओं के वकील तथा राज्य के लिए एल.डी. ए.पी.पी.

27. हम पहले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं तथा संक्षेप में यह खुलासा करते हैं कि मृतक तथा सूचक द्वारा अभियुक्तों द्वारा सरसों की फसल काटने का विरोध करने पर, पक्षों के बीच मौखिक विवाद हुआ तथा उसके बाद मार-पीट हुई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों ने मृतक तथा अ.सा. -4 (लाल बाबू सिंह) तथा अ.सा.-7 (बीरेन्द्र सिंह) जो मृतक को बचाने के लिए बीच-बचाव कर रहे थे, पर लाठी, डंडा, फरसा आदि अपने-अपने हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए।

28. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्ष में परीक्षित दस गवाहों में से अ.सा.-1 जालिम सिंह, अ.सा.-2 जूली कुमारी, अ.सा.-3 प्रमोद कुमार सिंह, अ.सा.-4 लाल बाबू सिंह तथा अ.सा.-7 बीरेन्द्र सिंह ने उक्त घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया है। वर्तमान मामले के गवाहों के साक्ष्य के संबंध में पूर्व पैराग्राफों में की गई चर्चा पर

विचार करने पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है तथा उनकी जिरह में कोई ऐसा पर्याप्त विरोधाभास नहीं पाया गया है जिससे उनकी गवाही की सत्यता पर संदेह हो। अ.सा.-1 जालिम सिंह एक स्वाभाविक गवाह प्रतीत होता है, क्योंकि घटना के समय वह अपने *बाथटब* में था, इसलिए उसने घटना देखी थी। जैसा कि पहले बताया गया है, सूचक लाल बाबू सिंह के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अ.सा. -1 का *बथान* घटनास्थल के निकट ही है तथा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीच में कोई मकान नहीं है। इस मामले को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अ.सा. -1 घटनास्थल को देखने की स्थिति में नहीं था। जहां तक अ.सा. -2 का प्रश्न है, यद्यपि उसने अपने मुख्य परीक्षण में घटनास्थल का प्रत्यक्षदर्शी होने का विवरण दिया है, परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में उसने केवल अपने पिता (मृतक) तथा अपने चाचा (सूचक) के घटनास्थल पर जाने की बात कही है तथा अपने बारे में बहुत सामान्य कथन दिया है कि वह खेत पर जाती है। इससे हमें कुछ संदेह होता है कि इस साक्षी ने वास्तव में घटनास्थल को देखा था या नहीं। हालांकि, बचाव पक्ष अपनी जिरह में कोई विरोधाभास नहीं ला पाया, जिससे उसके साक्ष्य पर सवाल उठाया जा सके, इसलिए उसके साक्ष्य को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अ. सा.-3, प्रमोद कुमार सिंह के साक्ष्य से पता चलता है कि एक समय वह घर पर था और घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने मृतक राज किशोर सिंह को खून से लथपथ पाया। हालांकि, उसने यह भी गवाही दी है कि उसने मृतक राज किशोर सिंह पर हमला होते देखा था, लेकिन यह नहीं बता सकता कि सूचनाकर्ता लाल बाबू सिंह पर किसने हमला किया। एक बार फिर, यह एक तथ्य है कि उसकी बहुत ही संक्षिप्त जिरह में विरोधाभास के रूप में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया, जिससे घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति पर संदेह हो, भले ही घटना के समय नहीं, लेकिन उसके तुरंत बाद।

29. हम अ. सा.-4 लाल बाबू सिंह और अ. सा.-7 बीरेंद्र सिंह के साक्ष्य पर अलग-अलग गौर करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी गवाही ही इस बात को पुख्ता करने के लिए पर्याप्त है कि आरोपी लाल बाबू सिंह पर हमला किसने किया। अपीलकर्ताओं को अपना अपराध सिद्ध करने के लिए, अ. सा.-5 डॉ. धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, जिन्होंने इन दोनों गवाहों की चोटों की जांच की थी, के पुष्टिकारक साक्ष्य पर भरोसा करने के अलावा, अ. सा.-4 (लाल बाबू सिंह), सूचक होने के नाते, अपने फर्दबयान में अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी बयान की है और अपने बयान में मुकदमे के दौरान अपने कथन पर कायम रहा है। अ. सा.-7 बीरेन्द्र सिंह ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और वह फर्दबयान (प्रदर्श-1/1) के हस्ताक्षरकर्ता होने के अलावा, फर्दबयान में ही एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में नामित किया गया है, जो बगल के खेत में काम कर रहा था और अभियुक्त व्यक्तियों के हाथों घायल भी हुआ था। यह गवाह जिरह की कसौटी पर खरा उतरा है और हमें उसके साक्ष्य में कोई अस्पष्टता नहीं मिली है जिससे घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति पर संदेह हो। इस समय अ. सा.-5, डॉ. धीरेन्द्र प्रसाद सिंह के साक्ष्य का संदर्भ लेना भी उचित होगा, क्योंकि वे ही वह डॉक्टर हैं जिन्होंने अ. सा.-4 लाल बाबू सिंह और अ. सा.-7 बीरेन्द्र सिंह दोनों की चोटों की जांच की थी और चोट रिपोर्ट को क्रमशः प्रदर्श-2 और प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नित किया गया है। यद्यपि दोनों गवाहों को लगी चोटें, निस्संदेह, साधारण प्रकृति की हैं, लेकिन अ. सा.-7 (बीरेन्द्र सिंह) के शरीर पर कठोर और कुंद पदार्थ की तीन चोटें और अ. सा.-4 (लाल बाबू सिंह) के शरीर पर कम से कम चार चोटें हैं, जिनमें से दो चोटें धारदार हथियार से लगी बताई गई हैं, जबकि डॉक्टर ने आगे स्पष्टीकरण दिया है कि ये दो चोटें धारदार हथियार जैसे फरसा से लगी हो सकती हैं। विचरण न्यायालय के रिकॉर्ड से पता चलता है कि बार-बार बुलाने पर भी इस गवाह से जिरह करने के लिए कोई नहीं आया, इसलिए चोट की रिपोर्ट के मिलीभगत से होने पर कोई सवाल

नहीं उठाया जा सकता। अ. सा. -4 (लाल बाबू सिंह) और अ. सा. -7 (बीरेंद्र सिंह) के साक्ष्य को अ. सा. -5 (डॉ. धीरेंद्र प्रसाद सिंह) के साक्ष्य के साथ पढ़ने पर यह तथ्य निर्णायक रूप से स्थापित होता है कि इन दोनों गवाहों को संबंधित घटना के दौरान अभियुक्तों के हाथों चोटें आई थीं।

30. इस प्रकार, उपर्युक्त दो गवाहों, अर्थात अ. सा. -4 और अ. सा. -7 को सुरक्षित रूप से घायल चश्मदीद गवाहों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि घायल गवाहों को विशेष दर्जा दिया गया है और वे अत्यंत मूल्यवान साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य*** के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जो ***(2010) 10 एससीसी 259*** में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें यह माना गया है कि जहां घटना का गवाह खुद घटना में घायल हो गया है, ऐसे गवाह की गवाही को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा गवाह है जो अपराध के दृश्य पर अपनी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी के साथ आता है और किसी को झूठा फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर (हमलावरों) को छोड़ने की संभावना नहीं है। यह बहुत सही माना गया है कि घायल गवाह को बदनाम करने के लिए पुख्ता सबूत की आवश्यकता होती है। हम इस मामले में नीचे दिए गए फैसले के पैरा संख्या 29 और 30 को उद्धृत करना उचित समझते हैं:-

> "29. इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय, *जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य* [(2009) 9 एससीसी 719: (2010) 1 एससीसी (क्रि) 107] में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था, जहाँ इस न्यायालय ने एक घायल अभियुक्त की गवाही के आधार पर विशेष साक्ष्य स्थिति को दोहराया था और अपने पहले के निर्णयों पर भरोसा करते हुए निम्नानुसार माना था:

(एससीसी पृष्ठ 726-27, पैरा 28-29)

"28. दर्शन सिंह (अ. सा. 4) एक घायल गवाह था। डॉक्टर ने उसकी जाँच की थी। उसकी गवाही को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उसने घटना का पूरा विवरण दिया था क्योंकि वह उस समय मौजूद था जब हमलावर ट्यूबवेल पर पहुंचे थे। *शिवलिंगप्पा कल्लयनप्पा बनाम कर्नाटक राज्य* [1994 सप (3) एससीसी 235: 1994 एससीसी (क्रि) 1694] में इस न्यायालय ने माना है कि घायल गवाह के बयान पर भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि उसके साक्ष्य को प्रमुख विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर अस्वीकार करने के लिए मजबूत आधार न हों, क्योंकि यदि यह साबित हो जाता है कि उसे उक्त घटना के दौरान चोट लगी थी तो घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति स्थापित हो जाती है।

29. *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशन चंद* [(2004) 7 एससीसी 629: 2004 एससीसी (क्रि) 2013] में इसी तरह के दृष्टिकोण को दोहराया गया है जिसमें कहा गया है कि मुहर लगे गवाह की गवाही की अपनी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता होती है। यह तथ्य कि गवाह को घटना के समय और स्थान पर चोटें आईं, उसकी गवाही का समर्थन करता है कि वह घटना के दौरान मौजूद था। यदि घायल गवाह से लंबी जिरह की जाती है और उसकी गवाही को खारिज करने के लिए कुछ भी नहीं निकाला जा सकता है, तो इस पर भरोसा किया जाना चाहिए (देखें *कृष्ण बनाम हरियाणा राज्य* [(2006) 12 एससीसी 459: (2007) 2 एससीसी (क्रि) 214])। इस प्रकार, हमारा यह मानना है कि दर्शन सिंह (अ. सा. 4) के साक्ष्य पर निचली अदालतों द्वारा सही ढंग से भरोसा किया गया है।"

> **30.** इस मुद्दे पर कानून को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है कि घायल गवाह की गवाही को कानून में विशेष दर्जा दिया गया है। यह इस तथ्य के परिणामस्वरूप है कि गवाह को लगी चोट अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी है और क्योंकि गवाह अपने वास्तविक हमलावर को केवल तीसरे पक्ष को अपराध के लिए गलत तरीके से फंसाने के लिए दंडित किए बिना नहीं जाने देना चाहेगा। इस प्रकार, घायल गवाह के बयान पर भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि उसके साक्ष्य को प्रमुख विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर अस्वीकार करने के लिए मजबूत आधार न हों।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***बीरबल नाथ बनाम*** के मामले में घायल चश्मदीद गवाह की स्थिति पर भी चर्चा की गई है। ***राजस्थान राज्य ने 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1396*** में रिपोर्ट की, जिसमें यह माना गया है कि एक घायल गवाह को अधिक साक्ष्य मूल्य दिया जाता है जब तक कि उस पर संदेह करने के लिए बाध्यकारी कारण मौजूद न हों। हम नीचे दिए गए उक्त निर्णय के पैरा संख्या 26 को उद्धृत करना उचित समझते हैं:-

> "**26.** उच्च न्यायालय ने तथ्यों के साथ-साथ कानून के आधार पर भी मामले की अपनी समझ में गलती की है। एक घायल चश्मदीद गवाह का बयान एक महत्वपूर्ण सबूत है जिसे अदालत द्वारा आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। छोटी-मोटी विसंगतियां मायने नहीं रखती हैं। *मध्य प्रदेश राज्य बनाम मानसिंह,* (2003) 10 एससीसी 414 में जहां विचरण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की सजा, अन्य बातों के साथ-साथ धारा 302 के तहत, एक घायल गवाह की तथाकथित विसंगतियों पर उच्च न्यायालय द्वारा अलग कर दी गई

थी, इस अदालत ने बरी किए जाने के खिलाफ राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए यह कहा:

"9. घायल गवाह के साक्ष्य का साक्ष्यात्मक महत्व अधिक है और जब तक कोई ठोस कारण न हो, उनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में चाकू का उल्लेख नहीं था, इससे घायल गवाह पीडब्ल्यू 4 और 7 द्वारा दिए गए साक्ष्य का प्रभाव खत्म नहीं हो जाता। मामूली विसंगतियां अन्यथा स्वीकार्य साक्ष्य की विश्वसनीयता को कम नहीं करती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा उजागर की गई परिस्थितियाँ घायल गवाहों के साक्ष्य के प्रति संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक है।"

32. अब अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिए गए अन्य तर्क पर विचार करना महत्वपूर्ण होगा कि चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए मौखिक विवरण की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि अपीलकर्ता संख्या 1 सचिदानंद सिंह द्वारा मृतक के सिर पर फरसा के माध्यम से हमला करने के विशिष्ट आरोप के विरुद्ध, मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. अरुण कुमार सिंह (अ. सा. -9) की राय में मृतक के सिर पर चोट किसी कठोर और कुंद वस्तु और उसके प्रभाव से लगी है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के इस तर्क के संबंध में, हम पाते हैं कि मृतक के शरीर पर पाए गए दो मृत्यु-पूर्व चोटें दोनों ही सिले हुए घाव थे और हिंसा की प्रकृति के संबंध में एक राय देने के अलावा, इस गवाह ने आगे कहा कि कठोर और कुंद वस्तु और उसके प्रभाव से हिंसा हुई थी। न्यायालय ने कहा कि चोट संख्या 1 और 2 के बारे में राय संबंधित सर्जन से प्राप्त की जा सकती है। यह तथ्य कि दो चोटें सिली हुई हैं, पोस्टमार्टम जांच करने वाले डॉक्टर के लिए हिंसा की प्रकृति के बारे में निर्णायक राय देना संभव नहीं था। जिरह में अ. सा.-9 (डॉ. अरुण कुमार सिंह)

ने आगे कहा है कि सिली जाने से पहले उन्हें चोट को देखने का अवसर नहीं मिला था। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि गिरने पर ऐसी चोट संभव नहीं होगी।

33. मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य के बीच संघर्ष से संबंधित कानून इस आशय से अच्छी तरह से स्थापित है कि जब तक चिकित्सा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य के साथ असंगत रूप से संघर्ष में न हो, तब तक चश्मदीद गवाहों की मौखिक गवाही पर संदेह नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***सोलंकी चिमनभाई उकाभाई बनाम गुजरात राज्य*** के मामले में ***एआईआर 1983 एससी 484*** में कहा है कि जब तक चिकित्सा साक्ष्य कथित तरीके से चोट लगने की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं कर देता, तब तक चश्मदीद गवाहों की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। इस निर्णय का संदर्भ **अब्दुल सईद** (ऊपर) के मामले में भी मिलता है। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क के संबंध में कि अभियोजन पक्ष का मामला मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कुछ संघर्ष के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है, खारिज किए जाने योग्य है। संपूर्ण मामले को समग्रता से देखते हुए तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सिर पर हमले का विशिष्ट आरोप है तथा तदनुसार सिर पर दो चोटें पाई गई हैं, साथ ही ओसीसीपिटल क्षेत्र पर खोपड़ी के नीचे हेमाटोमा पाया गया है तथा दाएं टेम्पोरल पैरिएटल क्षेत्र पर एक संचार फ्रैक्चर पाया गया है, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौखिक तथा चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई असंगत संघर्ष नहीं है जो अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यह भी विचार किया जाना चाहिए कि सिर की चोट मृतक की मृत्यु का कारण है।

34. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में जिन गवाहों की जांच की गई है, उनमें से अधिकांश

संबंधित गवाह हैं, इसलिए उन्हें भी हितबद्ध गवाह कहा जा सकता है। उपरोक्त तर्क के संबंध में यह निस्संदेह सत्य है कि यदि गवाह निकट संबंधी हैं, तो उनके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। हमने पूरी सावधानी और सतर्कता बरतते हुए अभियोजन पक्ष के गवाहों, खास तौर पर सुचक (अ. सा.-4) और बीरेंद्र सिंह (अ. सा.-7) के साक्ष्यों का विश्लेषण किया है, जो घायल चश्मदीद गवाह भी हैं और इस तरह के बेहतरीन गुणवत्ता वाले गवाहों के साक्ष्य की पृष्ठभूमि में अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर संदेह करना सुरक्षित और उचित नहीं होगा, खास तौर पर इस तथ्य के मद्देनजर कि बचाव पक्ष कोई बड़ा विरोधाभास उजागर करने में विफल रहा है। आखिरकार, किसी भी मामले के निर्णय पर सबूतों की मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता का असर होता है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का मामला शुरू से ही यह रहा है कि सुचक और मृतक को ही जमीन से जुड़ी कुछ बातचीत के लिए मैदान में बुलाया गया था और सुचक (अ. सा.-4) के अलावा, अ. सा.-1 (जालिम सिंह) और अ. सा.-7 (बीरेंद्र सिंह) प्राकृतिक गवाह थे, जो घटनास्थल के आसपास मौजूद थे और सभी ने संबंधित घटना को देखा था। यह एक बार फिर दोहराया गया है कि बचाव पक्ष गवाहों की जिरह से कोई भी ठोस विरोधाभास नहीं निकाल पाया है, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा सके। यह भी ध्यान में रखना होगा कि निकट संबंधी गवाह, जिन्हें चोटें भी आई हैं, वे कभी भी वास्तविक हमलावरों को बरी नहीं होने देंगे और उन लोगों को फंसाएंगे जो घटना में शामिल नहीं हैं।

35. संबंधित गवाह की विश्वसनीयता के मुद्दे के संबंध में, हम यह मानते हैं कि गवाहों को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है। पैराग्राफ नं. उद्धृत करने का अनुरोध किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए एक पुराने क्लासिक निर्णय की धारा 26, ***एआईआर 1953 एससी 364 (दलीप***

सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य) में रिपोर्ट की गई, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "**26.** एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आए जो दागी होने की संभावना है और इसका मतलब आम तौर पर यह होता है कि जब तक गवाह के पास आरोपी के खिलाफ दुश्मनी जैसे कारण न हों, उसे झूठा फंसाने की इच्छा न हो। आम तौर पर, एक करीबी रिश्तेदार असली अपराधी को पर्दा डालने और एक निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने वाला आखिरी व्यक्ति होगा। यह सच है, जब भावनाएँ प्रबल होती हैं और दुश्मनी के लिए व्यक्तिगत कारण होते हैं, तो एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी के साथ घसीटने की प्रवृत्ति होती है, जिसके खिलाफ गवाह के पास कोई दुश्मनी है, लेकिन ऐसी आलोचना के लिए आधार होना चाहिए और केवल संबंध का तथ्य आधार होने से बहुत दूर है सत्य की पक्की गारंटी। हालाँकि, हम कोई व्यापक सामान्यीकरण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का न्याय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारे अवलोकन केवल उन बातों का मुकाबला करने के लिए किए गए हैं जो अक्सर हमारे सामने आने वाले मामलों में विवेक के सामान्य नियम के रूप में सामने रखी जाती हैं। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामले को उसके अपने तथ्यों तक सीमित रखा जाना चाहिए और उसके द्वारा शासित होना चाहिए।"

36. बचाव पक्ष की ओर से उठाया गया एक और तर्क यह है कि मामले के जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है और उसकी गैर-परीक्षा ने बचाव पक्ष को नुकसान पहुंचाया है, हालांकि, जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा के कारण बचाव पक्ष को

होने वाले किसी भी पूर्वाग्रह को इंगित किए बिना केवल इस तरह के मुद्दे पर बहस करना कोई आधार नहीं रखता है। बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष के गवाहों की मौखिक गवाही पर कोई संदेह नहीं उठा पाया है और उसने ऐसे कोई सवाल भी नहीं उठाए हैं जो जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा के कारण होने वाले पूर्वाग्रह के मुद्दे से संबंधित हो सकते हैं।

37. जहां तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा के मुद्दे पर निर्धारित कानून का संबंध है, हम ***बिहारी प्रसाद बनाम बिहार राज्य*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला देंगे, ***(1996) 2 एससीसी*** में रिपोर्ट किया गया ***317: एआईआर 1996 एससी 2904,*** जिसमें यह माना गया है कि जांच अधिकारी की जांच न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है, खासकर तब जब अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह होने की संभावना नहीं है। उक्त निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभियुक्त को होने वाले पूर्वाग्रह का मामला मामले के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए और कोई सार्वभौमिक सीधा सूत्र नहीं बनाया जाना चाहिए कि जांच अधिकारी की जांच न करना आपराधिक मुकदमे को प्रभावित करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय में, ***बहादुर नाइक बनाम बिहार राज्य*** के मामले में ***(2000) 9 एससीसी 153*** में रिपोर्ट की है कि अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा का कोई महत्व नहीं है, जब कोई भौतिक विरोधाभास सामने नहीं आया है और यह भी नहीं दिखाया गया है कि इस तरह की गैर-परीक्षा के कारण अपीलकर्ता को क्या पूर्वाग्रह हुआ है, खासकर ऐसी स्थिति में जब अभियुक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता को हिला नहीं पाया है।

38. हालांकि, इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि कुछ ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा एक महत्वपूर्ण विचार बन जाएगी और

अभियोजन पक्ष को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए कि आपराधिक मामले के बेहतर न्यायनिर्णयन के लिए जांच अधिकारी गवाह के कठघरे में कदम रखे क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपराधिक कानून के लागू होने पर लगभग वहाँ होता है। हालांकि, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से घायल चश्मदीदों की ठोस, विश्वसनीय और अडिग गवाही की पृष्ठभूमि में, जांच अधिकारी की जांच न करने का मुद्दा पृष्ठभूमि में चला जाता है क्योंकि यह ज्यादा महत्व नहीं रखता है और वर्तमान मामले के तथ्यों में महत्वपूर्ण विचार नहीं बनता है।

39. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने खून से लथपथ मिट्टी और इस्तेमाल किए गए हथियारों की जब्ती न होने के संबंध में भी तर्क दिया है। इन तथ्यों को जांच एजेंसी की ओर से कुछ कमियां कहा जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से चश्मदीदों के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जिन्हें न्याय की आंख और कान कहा जाता है।

40. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने और उसके सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद, हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनके साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय, विश्वसनीय और विश्वसनीय हैं, इसलिए उनकी गवाही की वास्तविकता पर संदेह करने की कोई बात नहीं है, जिसके आधार पर विद्वान विचरण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है।

41. अब हम निम्नलिखित पर विचार करेंगे: अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए वैकल्पिक तर्क पर विचार करते हुए कि वर्तमान मामला धारा 300 भ.दं.सं. के दायरे में नहीं आता है, इसलिए हत्या के लिए सजा देने वाली धारा 302 भ.दं.सं. लागू नहीं होगी। बचाव पक्ष की ओर से उठाया गया तर्क यह है कि मृतक की मौत आवेश में अचानक हुई लड़ाई में हुई है और अपीलकर्ताओं का मृतक की हत्या करने का

कोई इरादा नहीं था, इसलिए मामले के इस दृष्टिकोण से, अपराध को धारा 304 भाग II भ.दं.सं. के तहत कवर किया जा सकता है न कि धारा 302 भ.दं.सं. के तहत। हमने अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए इस तर्क पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। जहां तक मामले के तथ्यों का सवाल है, यह न केवल अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता मृतक और उसके परिवार के खेत से सरसों की फसल काट रहे थे और यह प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच विवाद का कारण बन गया। घटना पक्षों के बीच मौखिक विवाद से शुरू हुई और तीखी नोकझोंक में बदल गई, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं ने मृतक और अन्य लोगों पर हमला कर दिया। मामले के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य और तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण बनने वाला कार्य इस ज्ञान के साथ किया गया था कि ऐसा कार्य मृत्यु का कारण बन सकता है, लेकिन तथ्य ऐसे नहीं हैं, जिससे मृतक की मृत्यु का कारण बनने के अपीलकर्ताओं के इरादे को स्थापित किया जा सके। "इरादा" और "ज्ञान" धारा 299 भ.दं.सं. के घटक हैं और जहां तक अभियुक्त द्वारा किया गया ऐसा कार्य है जो इस ज्ञान के साथ मृत्यु का कारण बनता है कि मृत्यु ऐसे कार्य से होने की संभावना है, लेकिन उनका मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था, तो यह धारा 304 भाग II भ.दं.सं. के दायरे में आएगा।

42. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और वर्तमान अपील में उठाए गए मुद्दों पर सुस्थापित कानून पर विचार करने के बाद, हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अपीलकर्ताओं की ओर से मृत्यु का कारण बनने के किसी भी इरादे के अभाव में वर्तमान मामले को हत्या नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह हत्या के बराबर न होने वाली गैर-इरादतन हत्या होगी।

43. हमने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया है और हम पाते हैं कि किसी विशेष शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा अनुपस्थित प्रतीत होता है और संपूर्ण घटना क्षण भर के आवेश में अचानक हुई लड़ाई में घटित हुई प्रतीत होती है और मृतक पर यह जानते हुए हमला किया गया था कि इससे शारीरिक चोट लगने की संभावना है जिससे मृतक की मृत्यु हो सकती है, लेकिन मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था। यह भी एक तथ्य है कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर (अ. सा.-9) ने भी यह स्पष्ट राय नहीं दी है कि मृतक को लगी दो चोटें सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। इस प्रकार, महत्वपूर्ण कारक जानबूझकर की गई चोट है जो सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

44. हम ***खोखन उर्फ खोखन विश्वास बनाम*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दे सकते हैं। ***छत्तीसगढ़ राज्य, (2021) 3 एससीसी 365*** में रिपोर्ट किया गया, जिसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ- 9 में धारा 300 भ.दं.सं. के अपवाद-4 पर विचार किया है और निम्नानुसार माना है:-

> "**9.** धारा 300 भ.दं.सं. दो भागों में है। पहला भाग वह है जब गैर इरादतन हत्या को हत्या कहा जा सकता है और दूसरा भाग अपवाद है जब गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं है। हमारे उद्देश्य के लिए धारा 300 भ.दं.सं. का प्रासंगिक भाग धारा 300 का खंड 4 और धारा 300 भ.दं.सं. का अपवाद 4 होगा। धारा 300 भ.दं.सं. के खंड 4 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो उसे पता है कि यह इतना खतरनाक है कि इससे, सभी संभावनाओं में, मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट लग सकती है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है, और

वह ऐसा कार्य बिना किसी बहाने के करता है, जिससे मृत्यु होने का जोखिम हो सकता है। मृत्यु या ऐसी चोट, ऐसी सदोष हत्या को हत्या कहा जा सकता है। हालांकि, धारा 300 के अपवाद 4 के अनुसार, सदोष हत्या तब हत्या नहीं होती है जब यह अचानक झगड़े में बिना सोचे-समझे की गई हो और अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया हो या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया हो। भ.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 के स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे मामलों में यह महत्वहीन है कि कौन सा पक्ष उकसावे की पेशकश करता है या पहला हमला करता है।"

45. ***लिट्टा सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, (2015) 15 एससीसी 327*** में रिपोर्ट की गई, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को 304 भाग II भ.दं.सं. में परिवर्तित करते हुए निम्नानुसार माना है:-

"**23.** मृतक को लगी चोट की प्रकृति और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार यानी लाठी और गंडासी (दरांती) को देखते हुए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने मृतक पर यह जानते हुए हमला किया था कि चोट लगने से उसे गंभीर चोट लग सकती है। व्यक्ति की मृत्यु। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष की ओर से कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्तों ने मृत्यु का कारण बनने की पूर्व योजना बनाई थी और उस इरादे से वे मृतक के खेत से आने का इंतजार कर रहे थे और फिर मृतक को मारने के इरादे से उन्होंने उस पर हमला किया।

24. यह कानून का एक सुस्थापित प्रस्ताव है कि मृत्यु का कारण बनने का इरादा, यह जानते हुए कि मृत्यु संभवतः होगी, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि मृत्यु

वास्तव में मृत्यु का कारण बनने के इरादे से या यह जानते हुए कि मृत्यु संभवतः होगी, हत्या है। गवाहों की गवाही से यह पता नहीं चलता है कि अभियुक्तों का इरादा मृत्यु का कारण बनना था और उस इरादे से उन्होंने मृतक के शरीर पर चोटें पहुंचाना शुरू कर दिया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब वे मृतक को पीट रहे थे, तो गवाह उस स्थान पर पहुंच गए और चिल्लाए, जिसके बाद अभियुक्तों ने मृतक को मारने के इरादे से और अधिक चोटें पहुंचाने के बजाय तुरंत भाग गए।

26. समस्त साक्ष्यों का विश्लेषण करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि घटना अचानक हुई तथा अपीलकर्ताओं की ओर से कोई पूर्व-योजना नहीं थी। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक को मारने के इरादे से उस पर हमला करने के लिए विशेष तैयारी की थी। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक पर इस तरह से हमला किया कि मृतक को गंभीर चोटें आईं जो मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन हम इस बात से आश्वस्त हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक को मारने के इरादे से चोट नहीं पहुंचाई गई थी।

27. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय में, वर्तमान मामला ऊपर बताए अनुसार धारा 304 भाग II भ.दं.सं. के अंतर्गत आता है। यद्यपि अपीलकर्ताओं का किसी की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं को पता था कि इस तरह की शारीरिक चोट से मृत्यु होने की संभावना है, इसलिए अपीलकर्ता गैर इरादतन हत्या के दोषी हैं और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत दंडित किया जा सकता है।"

46. सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक को जान से मारने की नीयत से उस पर हमला करने के लिए विशेष तैयारी की थी, बल्कि यह घटना मौखिक विवाद और तीखी नोकझोंक के पश्चात घटित हुई, जबकि अपीलकर्ताओं के पास उस समय तक कोई हथियार नहीं था। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुसार अपीलकर्ता सरसों की फसल काटने में व्यस्त थे, जिस पर सूचक और मृतक ने आपत्ति की और उसके पश्चात मौखिक विवाद गंभीर रूप लेने लगा और 'मारपीट' शुरू हो गई, जिसमें अपीलकर्ताओं ने हमला करने के लिए हथियार उठा लिए और मृतक पर वार कर उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं, इसके अतिरिक्त दो अन्य गवाहों अ.सा. -4 (सूचक) और अ.सा. -7 (बीरेन्द्र सिंह) को भी चोटें पहुंचाईं, जब उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया।

47. इस प्रकार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मामले और विषय-वस्तु पर प्रचलित कानून के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत आता है, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से मृतक की हत्या करने का इरादा स्थापित नहीं होता है और इसके अलावा, अभियोजन पक्ष न तो मृतक की हत्या करने के लिए अपीलकर्ताओं के पूर्व-निर्धारित मन की उपस्थिति को स्थापित करने में सक्षम है और न ही आरोपित किया है। ऐसा लगता है कि पूरी घटना क्षण भर के आवेश में अचानक हुई लड़ाई में और आवेश में हुई है, इसलिए मृतक की हत्या करने के इरादे का तत्व गायब लगता है।

48. इसलिए, अभियोजन पक्ष के मामले और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के बाद, हम महसूस करते हैं कि अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार, धारा

302/149 भ.दं.सं. के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और उसके तहत आजीवन कारावास की सजा तथा 10,000/- रुपये का जुर्माना रद्द किया जाता है और इसके बजाय अपीलकर्ताओं को भ.दं.सं. की धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराया जाता है। हालांकि, धारा 147, 148, 323 और 324 भ.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि अपीलकर्ताओं के खिलाफ होगी, लेकिन उसके तहत कोई अलग से सजा नहीं दी जाएगी।

49. सजा वाले हिस्से पर आने से पहले, हम कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख करना चाहेंगे, जिनमें अभियुक्तों की दोषसिद्धि को धारा 302 भ.दं.सं. से धारा 304 भाग II भ.दं.सं. के तहत बदल दिया गया है और अधिकतम सजा से कम सजा दी गई है या अभियुक्तों को उनके द्वारा पहले से काटी गई हिरासत अवधि से गुजरने की सजा दी गई है।

50. ***रणधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य*** के मामले में ***एआईआर 1982 एससी 55*** में रिपोर्ट की गई, सजा में बदलाव करते हुए परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए अपीलकर्ता की धारा 302 भ.दं.सं. से धारा 304 भाग II भ.दं.सं. में आजीवन कारावास की सजा को घटाकर पांच वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया गया। मामले के तथ्य यह थे कि अपीलकर्ता ने मृतक के सिर पर कस्सी से वार किया था, जिससे उसके सिर पर चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 और 10 को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

> "**9.** हमारी राय में, परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए अर्थात केवल एक ही चोट है, कि अपीलकर्ता द्वारा हथियार पहले से नहीं लाया गया था, कि कोई पूर्व-योजना नहीं थी, कि वह एक युवा कॉलेज जाने वाला लड़का था, कि मृतक और उसके पिता के बीच कुछ विवाद हुआ था और मृत्यु लगभग छह दिन बाद हुई थी, कोई केवल यह कह सकता है कि अपीलकर्ता को इस बात का ज्ञान होना

> चाहिए कि वह ऐसी चोट पहुँचाने वाला था जिससे मृत्यु होने की संभावना थी। इन परिस्थितियों में, हमारी राय में, अपीलकर्ता ने दंड संहिता, 1860 की धारा 304 भाग II के तहत अपराध किया है और उसे इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए और पांच साल के कठोर कारावास की सजा दी जानी चाहिए।
>
> **10.** तदनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को उचित ठहराया जाता है। धारा 302 से धारा 304 भाग II में परिवर्तन किया गया है, तथा आजीवन कारावास की सजा को घटाकर पांच वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया गया है।

51. हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ***(2018) 8 एससीसी 228 (दीपक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य)*** में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें तथ्य यह थे कि मृतक के पसलियों के क्षेत्र में अपीलकर्ता द्वारा तलवार से किए गए हमले से एक छेद हो गया था और इसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई थी। मामले का समर्थन एक घायल गवाह और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा भी किया गया था। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे साक्ष्य पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि घटना बिना किसी पूर्व-योजना के क्षणिक आवेश में घटित हुई थी, इसलिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को धारा 302 भ.दं.सं. से धारा 304 भाग II भ.दं.सं. में बदल दिया गया और साथ ही अभियुक्त द्वारा पहले से ही बिताई गई हिरासत अवधि के अनुसार सजा में भी बदलाव किया गया। निर्णय के पैराग्राफ-7 और 8 को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

> "**7.** साक्ष्य की संपूर्णता पर विचार करने पर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घटना क्षण की गर्मी में हुई और हमला बिना किसी पूर्व विचार के समय पर किया गया। यह तथ्य कि अपीलकर्ता सड़क के उस पार अपने घर की ओर भागा और तलवार

लेकर लौटा, हत्या करने के इरादे का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि घटना की उत्पत्ति और अपीलकर्ता द्वारा एक बार किया गया हमला, साथ ही पूरे प्रकरण की अवधि 11/2 से 2 मिनट है। यदि मृतक के जीवन को समाप्त करने का कोई इरादा था, तो अपीलकर्ता को भागने के बजाय उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए दूसरा हमला करने से कोई नहीं रोक सकता था। ऐसा लगता है कि इरादा एक नाराज पड़ोसी द्वारा तेज आवाज में बजाई गई आवाज के कारण गुस्सा निकालकर सबक सिखाने का था। टेप रिकॉर्डर। लेकिन इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, पसलियों के क्षेत्र में किए गए हमले, इस ज्ञान के आधार पर कि मौत होने की संभावना थी, अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

8. साक्ष्य, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता में, हम धारा 302 भ.दं.सं. के तहत अपीलकर्ता की सजा को बनाए रखने में असमर्थ हैं और संतुष्ट हैं कि इसे धारा 304 भाग II भ.दं.सं. में बदला जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया जाता है। उसकी सजा के बाद हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए, हम सजा को पहले से ही हिरासत की अवधि में बदल देते हैं। यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है तो अपीलकर्ता को तुरंत रिहा किया जा सकता है।

52. हम ***जोसेफ बनाम केरल राज्य*** के मामले का भी उल्लेख करना चाहेंगे, जिसकी रिपोर्ट ***1995 एससीसी (सीआरआइ) 165*** में की गई थी, जिसमें आरोपी ने जुए में पैसे के दांव को लेकर आपस में हुई तीखी बहस के बाद मृतक पर लाठी से हमला किया था और मृतक के सिर पर दो वार किए थे, जिसके परिणामस्वरूप मृतक जमीन पर गिर गया था। आरोपी ने फिर मृतक पर तीसरा वार किया था, लेकिन वह चूक

गया था। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि पूरी घटना एक मामूली घटना का परिणाम थी और ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता था कि आरोपी, जिसने मृतक के सिर पर दो लाठी वार किए थे, का इरादा इतनी चोट पहुंचाना था कि उसकी मृत्यु हो जाए। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि उसे पता था कि ऐसी चोटें पहुंचाने से उसकी मृत्यु हो सकती है। मामले के इस दृष्टिकोण से, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए गैर इरादतन हत्या करने का दोषी हत्या के आरोप में उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराया गया और उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जैसा कि उक्त निर्णय के पैराग्राफ '3' में दर्ज है।

53. ***एन. रामकुमार बनाम राज्य प्रतिनिधि निरीक्षक*** के मामले में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें ***सीआर अपील संख्या 2006/2023*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के पूरे मामले पर विचार करते हुए अपीलकर्ता की सजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से बदलकर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत कर दिया और उसे उसके द्वारा पहले से काटी गई अवधि तक कारावास की सजा सुनाई। प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 20 और 21 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

> "20. इस प्रकार, धारा 302 के तहत लगाए गए दंड को धारा 304 भाग II में परिवर्तित करने के लिए ऊपर विश्लेषण किए गए केस लॉ से यह उभर कर आता है कि परीक्षण के दौरान सामने आए तथ्यों को देखा जाना चाहिए। मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि मृत्यु का कारण बनने या घटना की उत्पत्ति और अभियुक्त द्वारा एकल हमला और पूरे प्रकरण की अवधि के लिए कोई पूर्व-योजना नहीं थी, जो इरादे को निर्धारित करने के कारक थे। अपराध को धारा 304 भाग-

॥ भ.दं.सं. के दायरे में स्पष्ट रूप से लाया जा सकता है। वर्तमान मामले में यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता और मृतका एक दूसरे से प्यार करते थे। तथ्य यह है कि मृतका ने अपीलकर्ता से बात करना बंद कर दिया था और वह अपने पड़ोसी श्री सुधाकर से बात कर रही थी, जिसने अपीलकर्ता के मन में मृतका के आचरण के बारे में गुस्सा पैदा कर दिया था। मृतका के इस व्यवहार में आए परिवर्तन से वह परेशान था। अ. सा.-1, जो कोई और नहीं बल्कि मृतका की मां है, की गवाही के अनुसार भी अपीलकर्ता और मृतका के बीच विवाद हुआ था और उनके प्रेम संबंधों के संबंध में अपीलकर्ता और मृतका के बीच शब्दों का आदान-प्रदान हुआ था। अपीलकर्ता द्वारा यह पूछे जाने पर कि अभियुक्त ने उससे बात करना क्यों बंद कर दिया था और वह सुधाकर के साथ दोस्ती क्यों बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और मृतका द्वारा दिए गए उत्तर के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता क्रोधित हो गया और उसी क्षण उसने उसके बाल पकड़े और उसका सिर दीवार पर दे मारा जिससे खून बहने लगा और यह देखकर वह घटनास्थल से भाग गया। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा किया गया एक बार का हमला और पूरी अवधि लगभग 2-3 मिनट तक चली, यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसका मृतका को मारने का इरादा था। यदि मृतका की जान लेने का कोई इरादा होता तो जाहिर है अपीलकर्ता पूरी तैयारी के साथ आता और मृतका पर पूर्व-योजना के तहत हमला करता। एक और पहलू जिस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, वह यह कि अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से मृतका से संपर्क किया था और उससे यह पूछने का इरादा किया था कि वह उससे बात क्यों नहीं कर रही है, जबकि वे दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और साथ ही वह श्री सुधाकर (पड़ोसी) के साथ उसकी

मित्रता के बारे में संदेह को दूर करना चाहता था और इस तथ्यात्मक परिदृश्य में, तीखी नोकझोंक हुई और उसके जवाब से क्रोधित होकर अपीलकर्ता ने गुस्से में अपना सिर दीवार पर पटक दिया, जिससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसका उसकी जान लेने का कोई इरादा था, खासकर तब जब वह उससे प्यार करता था।

21. कानून और तथ्यों के उपर्युक्त विश्लेषण में, हमारा विचार है कि वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है। अपीलकर्ता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित दोषसिद्धि के लिए अपीलकर्ता को पहले से ही काटी गई अवधि तक कारावास की सजा सुनाई जाती है और यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

54. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***(2011)14 एस.सी.सी. 471 (बुद्धू सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य)*** में दिए गए निर्णय का संदर्भ देना भी समीचीन होगा, जिसमें एक बार फिर धारा 302 आई.पी.सी. से धारा 304 भाग II आई.पी.सी. में दोषसिद्धि के परिवर्तन का मुद्दा उठाया गया था, यद्यपि मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से वार करने से मृत्यु हुई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इरादे के तत्व की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए, माना कि अपराध गैर इरादतन हत्या है और अभियुक्तों की दोषसिद्धि को धारा 302 आई.पी.सी. से धारा 304 भाग II आई.पी.सी. में परिवर्तित कर दिया और उनमें से प्रत्येक को पहले से ही भुगती गई अवधि की सजा सुनाई। हम नीचे उक्त निर्णय के पैराग्राफ-8 और 9 को उद्धृत करना उचित समझते हैं:-

"**8.** समग्र सामग्री पर विचार करते हुए, हमारा मानना है कि अभियुक्त लेदवा सिंह और बालचंद सिंह के खिलाफ़ रिकॉर्ड में शायद

ही कुछ कहा जा सके, हालाँकि उनकी ओर से साझा इरादे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि उन्होंने मृतक के साथ हाथापाई और उसे नीचे गिराने का खुला कार्य किया था। अब, यह देखते हुए कि उसके पिता और भाई मृतक के साथ हाथापाई कर रहे थे, अभियुक्त बुद्धू सिंह ने कुल्हाड़ी से हमला किया- सिर पर वार करना जानबूझकर नहीं कहा जा सकता। वार कहीं भी लग सकता था। हालांकि, वार मृतक के सिर पर लगा। इसलिए, इरादे के तत्व को खारिज किया जाता है। फिर से अभियुक्त की ओर से उठाया गया बचाव यह तर्क देता है कि मृतक की हत्या करने का इरादा नहीं हो सकता है, यह इस तथ्य से उचित है कि अभियुक्त बुद्धू सिंह ने हमला दोबारा नहीं किया। परिस्थितियों के तहत, हमें लगता है कि अभियोजन पक्ष धारा 304 भाग II भ.दं.सं. के तहत अभियुक्तों के अपराध को साबित करने में सक्षम है।

9. हम, तदनुसार, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को संशोधित करते हैं और अभियुक्तों की सजा को धारा 302 भ.दं.सं. से धारा 304 भाग II भ.दं.सं. में परिवर्तित करते हैं और उनमें से प्रत्येक को पहले से ही भुगती गई अवधि की सजा देते हैं। आरोपी बुद्धू सिंह पिछले पांच साल से जेल में बंद बताया गया है जबकि अन्य आरोपी लेदवा सिंह और बालचंद सिंह पिछले दस साल से जेल में बंद बताए गए हैं। उन्हें तत्काल जेल से रिहा किया जाए, जब तक कि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो।

55. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त न्यायिक निर्णयों में निर्धारित कानून के मद्देनजर, हम उचित सजा देने के उद्देश्य से वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी सावधानीपूर्वक विचार करना चाहेंगे।

56. वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां दर्शाती हैं कि अपीलकर्ताओं ने सूचना देने वाले और मृतक को संबंधित भूमि से संबंधित कुछ बातचीत करने के उद्देश्य से खेत में बुलाया था। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि सूचना देने वाले और मृतक के घटनास्थल पर पहुंचने पर अपीलकर्ता हथियारबंद थे, बल्कि वे सरसों की फसल काटने में लगे हुए थे, जिस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई थी। यह भी एक तथ्य है, जिसे साक्ष्य में भी स्वीकार किया गया है कि आरोपी व्यक्ति फसल काटने के लिए दरांती (जो तेज धार वाला हथियार है) का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अभियोजन पक्ष पर हमला करने के उद्देश्य से इसका उपयोग नहीं किया। बाद में ही लाठी, डंडा और फरसा जैसे हथियार हमले के लिए उठाए गए थे, पक्षों के बीच विवाद गंभीर रूप लेने लगा। इसके अलावा, एफआईआर में ही यह संकेत दिया गया कि मारपीट की पूरी घटना के बाद अपीलकर्ताओं ने सरसों की फसल को ट्रैक्टर में लोड किया, जिससे पता चलता है कि वे केवल इसी उद्देश्य से खेत में आए थे और उनका किसी की हत्या या शारीरिक चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।

57. अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 द्वारा केवल लाठी मारने और वह भी ट्रैक्टर से बाद में लाठी निकालने के तथ्य से यह स्पष्ट है कि उनका किसी को गंभीर चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, मौत का कारण बनना तो दूर की बात है। यह देखा जाएगा कि मृतक के सिर पर केवल दो चोटें आई थीं, हालांकि वे गंभीर प्रकृति की थीं और डॉक्टर या अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के अनुसार उसके शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं पाई गई। इससे हम इस विवेकपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं ने कभी भी हमला करने की योजना नहीं बनाई या पूर्व-नियोजित नहीं था, ऐसा कार्य करने की तो बिल्कुल भी नहीं जो मृतक की मृत्यु का कारण बनता। इससे अभियोजन पक्ष के लिए मृत्यु या किसी भी प्रकार की गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे का तत्व समाप्त हो जाता है और सरसों की फसल

काटने से अभियुक्तों को सुचक और मृतक द्वारा दिए गए प्रतिरोध के परिणामस्वरूप जो कुछ भी हुआ, वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिससे जान का नुकसान हुआ, जो अचानक लड़ाई और आवेश में क्षण भर में हुई।

58. चिकित्सा साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि मृतक की तत्काल मृत्यु नहीं हुई बल्कि उसे अस्पताल ले जाया गया और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अन्य दो घायल चश्मदीद गवाह अ.सा.-4 (सुचक) और अ.सा.-7 (बीरेंद्र सिंह) को भी शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर साधारण चोटें आईं। यह इस तथ्य का भी संकेत है कि किसी को भी गंभीर चोट पहुंचाने की कोई मंशा नहीं थी।

59. हमने साक्ष्य से यह भी देखा है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अपीलकर्ता संख्या 1 सचिदानंद सिंह के संबंध में विशेष आरोप लगाए हैं, जो फरसा से लैस था, जिसने सुचक और मृतक पर हमला किया था, जबकि अन्य अभियुक्तों के संबंध में लाठी से हमला करने के सामान्य आरोप लगाए गए हैं, जिसमें अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 भी शामिल हैं, लेकिन हमले के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। दोनों घायल चश्मदीद गवाहों अ. सा.-4 (सुचक) और अ. सा.-7 (बीरेंद्र सिंह) के साक्ष्यों का अवलोकन इस तथ्य की पुष्टि करेगा।

60. हम इस तथ्य पर भी विचार कर सकते हैं कि घटना वर्ष 2000 के फरवरी माह में घटित हुई थी, इसलिए अपीलकर्ताओं को काफी लंबी अवधि तक मुकदमे की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अंततः वर्ष 2016 में उन्हें दोषी ठहराया गया। धारा 313 सीआरपीसी के तहत उनके बयान दर्ज करने के समय, वे 50 से 55 वर्ष की आयु के थे। अब, दोषसिद्धि की तिथि से 9 वर्ष और घटना की तिथि से 25 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद, वे या तो वरिष्ठ नागरिक बन गए हैं या उसी कगार पर खड़े हैं।

61. इस प्रकार, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता से उभरकर पूरे मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि अपीलकर्ता संख्या 1, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने फरसा से हमला किया था, 9 वर्षों से अधिक समय से हिरासत में है और अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 मितेंद्र सिंह और सत्येंद्र सिंह, जिनके बारे में आरोप है कि वे केवल लाठी से लैस थे और उन पर मृतक और दो घायल व्यक्तियों पर लाठी से प्रहार करने का सामान्य आरोप है, साढ़े चार वर्षों से हिरासत में हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान मामला भ.दं.सं. की धारा 304 के भाग II के अंतर्गत आएगा। इस मामले को देखते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत दोषी ठहराया जाना आवश्यक है, अतः अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाना तथा उसके अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा तथा 10,000/- रुपये का जुर्माना निरस्त किया जाता है तथा इसके स्थान पर अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है तथा परिवर्तित सजा के लिए अपीलकर्ताओं को पहले से ही बिताई गई हिरासत अवधि की सजा सुनाई जाती है।

62. अपीलकर्ता संख्या 1 सचिदानंद सिंह, जो हिरासत में है, को तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो। अपीलकर्ता संख्या 2 तथा 3 मितेंद्र सिंह तथा सत्येंद्र सिंह, क्रमशः जमानत पर हैं, अतः उन्हें जमानत बांध पत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

63. तदनुसार, अपील को ऊपर बताई गई सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

(सोनी श्रीवास्तव, न्यायमूर्त्ति)

मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्त्ति: मैं सहमत हूँ।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्त्ति)

एस.एस.बी/अरविंद -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।